भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4684

20 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

उदयपुर में एम्स की स्थापना

4684. श्री राजकुमार रोतः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में स्थापित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) की राज्यवार संख्या कितनी है, साथ ही उनकी स्वीकृति संबंधी तिथियाँ, चयन मानदंड, नियम और पात्रता दिशानिर्देश क्या हैं;

(ख) क्या राजस्थान के उदयपुर मंडल (जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ शामिल हैं) में सुपरस्पेशियलिटी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों को उपचार के लिए अन्य राज्यों या बड़े शहरों की यात्रा करनी पड़ती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का उदयपुर मंडल में एक एम्स की स्थापना किए जाने के लिए स्वीकृति देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए नियत समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) का उद्देश्य किफायती/विश्वसनीय विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाना है। पीएमएसएसवाई के तहत, अब तक देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिनमें राजस्थान के जोधपुर में स्थित एक एम्स भी शामिल है, जो कार्यशील है। एम्स का विवरण **अनुलग्नक-I** में है। इसके अलावा, राजस्थान में विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को सुदृढ़ और उन्नत करने के लिए, पीएमएसएसवाई के एक अन्य घटक के तहत, केंद्र-राज्य लागत साझाकरण के आधार पर निम्नलिखित सरकारी मेडिकल कॉलेजों के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक (एसएसबी) के निर्माण के माध्यम से उन्नयन को मंजूरी दी गई है: (i) आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर,

(ii) सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर, (iii) सरकारी मेडिकल कॉलेज, जयपुर, (iv) सरकारी मेडिकल कॉलेज, कोटा। पीएमएसएसवाई के तहत, राजस्थान के उदयपुर में एम्स की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, यह मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके समग्र संसाधन आवंटन के भीतर प्रस्तुत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के आधार पर उनकी स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। अब तक, राजस्थान राज्य को वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक ₹ 10,570.41 करोड़ की राशि निर्गत की जा चुकी है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-अभिम) के तहत राजस्थान के 33 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें उदयपुर मंडल के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिलों में 50 बिस्तरों वाले एक-एक सीसीबी शामिल हैं।

दिनांक 20 मार्च, 2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4684 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

पीएमएसएसवाई के अंतर्गत एम्स का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एम्स का स्थान	अनुमोदन का वर्ष
1	आंध्र प्रदेश	एम्स मंगलागिरी	2015
2	असम	एम्स गुवाहाटी	2017
3	बिहार	एम्स दरभंगा	2020
4		एम्स पटना	2006
5	छत्तीसगढ़	एम्स रायपुर	2006
6	गुजरात	एम्स राजकोट	2019
7	हरियाणा	एम्स माजरा (रेवाड़ी)	2019
8	हिमाचल प्रदेश	एम्स बिलासपुर	2018
9	जम्मू एवं कश्मीर	एम्स विजयपुर, जम्मू	2019
10		एम्स अवंतीपोरा, कश्मीर	2019
11	झारखंड	एम्स देवघर	2018
12	मध्य प्रदेश	एम्स भोपाल	2006
13	महाराष्ट्र	एम्स नागपुर	2015
14	ओडिशा	एम्स भुवनेश्वर	2006
15	पंजाब	एम्स बठिंडा	2016
16	राजस्थान	एम्स जोधपुर	2006
17	तमिलनाडु	एम्स मदुरै	2018
18	तेलंगाना	एम्स बीबीनगर	2018
19	उत्तर प्रदेश	एम्स रायबरेली	2009
20		एम्स गोरखपुर	2016
21	उत्तराखंड	एम्स ऋषिकेश	2006
22	पश्चिम बंगाल	एम्स, कल्याणी	2015

*****